भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

06.08.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2906 का उत्तर

अंगमाली-सबरी रेल परियोजना

2906. श्री हैबी ईडन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल रेल विकास निगम लिमिटेड (केआरडीसीएल) द्वारा अंगमाली-सबरी रेलवे लाइन परियोजना का क्रियान्वयन किए जाने की संभावना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या रेलवे की इस परियोजना के लिए अनुमानित समय-सीमा की जानकारी देने की योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे का इरादा इस परियोजना को पीएम गति शक्ति में शामिल करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने यह पाया है कि रेलवे बोर्ड द्वारा संशोधित अनुमानों को मंजूरी देने में देरी हुई है और यदि हाँ, तो इस देरी के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार परियोजना के समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पूरी प्रक्रिया में तेजी लाने की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): एरुमेली के रास्ते अंगमालि-सबरीमाला नई लाइन परियोजना को 1997-98 में स्वीकृति दी गई थी। अंगमालि-कालडि (7 कि.मी.) और कालडि-पेरुम्बवूर (10 कि.मी.) पर अधिक समय तक

चलने वाला कार्य शुरू कर दिए गए थे। बहरहाल, भूमि अधिग्रहण और लाइन के संरेखण के निर्धारण के विरुद्ध स्थानीय लोगों के विरोध, परियोजना के खिलाफ दायर अदालती मामलों और केरल राज्य सरकार से अपर्याप्त सहयोग के कारण इस परियोजना पर आगे काम नहीं किया जा सका।

परियोजना की अनुमानित लागत को 3801 करोड़ रुपए पर अद्यतन किया गया है और अनुमान की स्वीकृति और परियोजना की लागत साझा करने की इच्छा के लिए दिसंबर, 2023 में केरल सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

अगस्त, 2024 में केरल सरकार ने अपनी सशर्त सहमति प्रदान कर दी है। रेलवे ने केरल सरकार से लागत साझा करने के लिए बिना शर्त सहमति प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

केरल सरकार से इस परियोजना के लिए केरल राज्य सरकार, रेल मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने का भी अनुरोध किया गया है।

बहरहाल, केरल सरकार द्वारा 3 जून, 2025 को रेल मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में यह सूचित किया गया है कि केरल राज्य सरकार त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत नहीं है।

केरल के मुख्यमंत्री के साथ हाल ही में हुई बैठक में रेल मंत्री ने केरल सरकार से परियोजना की लागत में अपनी 50% हिस्सेदारी को भूमि अधिग्रहण में उपयोग करने का अनुरोध किया है। राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण शुरू करने के बाद कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है।

केरल राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार हैः

अवधि	परिव्यय
2009-14	372 करोड़ रु./वर्ष
2025-26	3,042 करोड़ (8 गुना से अधिक)

केरल राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का कार्य-निष्पादन भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण रुका हुआ है। केरल राज्य में भूमि अधिग्रहण की स्थिति निम्नानुसार हैः

केरल में परियोजनाओं के लिए अपेक्षित कुल भूमि	476 हेक्टेयर
अधिगृहीत भूमि	73 हेक्टेयर (15%)
अधिग्रहण के लिए शेष भूमि	403 हेक्टेयर (85%)

भारत सरकार परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए तैयार है, बहरहाल, इसकी सफलता केरल सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है। रेलवे ने भूमि अधिग्रहण के लिए केरल सरकार को ₹2,112 करोड़ जमा कराए हैं। भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए केरल सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, भूमि अधिग्रहण के कारण विलंबित कुछ प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कुल अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)	अधिगृहीत भूमि (हेक्टेयर में)	अधिग्रहण के लिए शेष भूमि (हेक्टेयर में)
1.	अंगमाली - सबरीमाला नई लाइन (111 कि.मी.)	416	24	392
2.	एर्णाकुलम - कुम्बलम खंड दोहरीकरण (8 कि.मी.)	4	3	1
3.	कुम्बलम - तुरवूर खंड दोहरीकरण (16 कि.मी.)	10	9	1
4.	त्रिवेंद्रम - कन्याकुमारी दोहरीकरण (87 कि.मी.)	41	36	5
5.	षोराणूर - वल्लतोल दोहरीकरण (10 कि.मी.)	5	0	5

भारत सरकार केरल में रेल नेटवर्क को मज़बूत बनाने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। केरल से गुज़रने वाले रेलवे नेटवर्क को मज़बूत बनाने के लिए, निम्नलिखित सर्वेक्षणों को स्वीकृत किया गया है:

क्र.सं.	मार्ग	लंबाई
1	मंगलूरु-षोरणूर तीसरी एवं चौथी लाइन	308 कि.मी.
2	षोरणूर- कोयम्बत्तूर तीसरी एवं चौथी लाइन	99 कि.मी.
3	षोरणूर-एरणाकुलम तीसरी लाइन	107 कि.मी.
4	एरणाकुलम-कायमकुलम तीसरी लाइन	115 कि.मी.
5	कायमकुलम- तिरुवनंतपुरम तीसरी लाइन	105 कि.मी.
6	तिरुवनंतपुरम-नागरकोविल तीसरी लाइन	71 कि.मी.

रेल परियोजना(ओं) का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना(ओं) स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, परियोजना कार्य स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजनाओं के पूरा होने के समय व लागत को प्रभावित करते हैं।

******